SHRIMATI VIPLOVE THAKUR: No, no. I am talking about the officers, not about the people. I am talking about those officers who were posted there at that time.

SHRI V. NARAYANASAMY: About the officers, we will be able to consider after the court judgment comes.

SHRIMATI KANIMOZHI: Is there any provision in the Act to make Delhi a heritage city? I would like to know about that.

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, under the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act 1958, there is no provision called heritage city, and only heritage sites, historical ancient monuments and archaeological sites have been mentioned in the Act. Now, Sir, they are bringing another Bill which is pending in the Rajya Sabha. The Standing Committee is also considering it. Now, the monuments which have not been coming under the purview of the Government of India and also the State Governments, to codify those monuments and for protecting them, there is a Bill which is pending in the Rajya Sabha because the existing Act covers the historical ancient monuments and the archaeological sites and remains which are more than 100 years old. For monuments which are less than 100 years old, the new Bill is coming, and as soon as the Bill comes, all this will be taken care of. There is no provision called the heritage city in the present Act.

*102. [The questioner (Miss Anusuiya Uikey) was absent. For answer *vide* page 21 *infra*]

*103. [The questioner(s) (Ms. Mabel Rebello, Dr. T. Subbarami Reddy) were absent. For answer *vide* page 23 *infra*]

*104. [The questioner (Shri Ramchandra Khuntia) was absent. For answer *vide* page 23 *infra*]

*105. [The questioner(s) (Shri Santosh Bagrodia, Shri Gireesh Kumar Sanghi) were absent. For answer *vide* page 26 *infra*]

Meeting of telecom service providers

*106. SHRIMATI MOHSINA KIDWAI:††
SHRI N.K. SINGH:

Will the Minister of COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY be pleased to state:

(a) whether Government had called a meeting of heads of all telecom service providers recently;

(b) if so, the details of the issues discussed in the meeting and the outcome thereof;

(c) whether the telecom service providers are not following the directives/guidelines of Government issued from time to time; and

††The question was actually asked on the floor of the House by Shrimati Mohsina Kidwai.

(d) if so, the facts thereof and the further steps Government proposes to take in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI SACHIN PILOT): (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) Yes, Sir. Meetings were held with Access Service Licensees, National Long Distance Service Licensees, International Long Distance Service Licensees, Internet Service Providers in the first week of November, 2009. Suggestions of the service providers were invited for the various measures which *inter-alia* include:—

(i) Steps to increase tele-density, specifically rural tele-density.

(ii) Measures for more effective utilization of Universal Service Obligation (USO) Fund.

(iii) Measures to be taken for faster Internet and Broadband coverage especially in rural areas.

(iv) Incentives for lower tariff for expansion of telecom services.

(c) and (d) While various service providers, generally, follow the directives/guidelines/ terms and conditions of the licence, however necessary action is taken as per the provisions of the licences granted to various service providers under section 4 of the Indian Telegraph Act in case of any non-compliance.

MR. CHAIRMAN: Q.No. 106.

श्रीमती मोहसिना किदवई: माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि उन्होंने मीटिंग में चर्चा की है कि रूरल एरियाज में किस तरह से टेली डेंसिटी बढ़ाई जाए और किस तरह से उसको और आगे गति दी जाए। मैं समझती हूं कि हमारी टेलीफोन इण्डस्ट्री का जो फैलाव है, बढ़ाव है, वह सब राजीव जी जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, उनकी ही देन है और उनका विजन था। मुझे खुशी है कि बहुत सी हमारी कम्पनीज जैसे एम0टी0एन0एल0 है, न सिर्फ अपने मुल्क में, बल्कि दुनिया में भी उसका नाम है। माननीय मंत्री जी ने मीटिंग में यह तय किया कि रूरल एरियाज में ज्यादा से ज्यादा काम किया जाएगा और वहां पर और फेसिलिटीज बढ़ाई जाएंगी। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि इस वक्त आपके पास कोई भी प्रोपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है। लेकिन यह खुशी की बात है कि आज हमारे रूरल एरियाज के लोग भी एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, दूसरे मुल्कों से बात कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त इतना पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसके बारे में मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि उन्होंने इस बारे में क्या कदम उठाए हैं, जिससे रूरल एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो सके? माननीय मंत्री जी से मैं एक और बात जानना चाहती हूं कि उनकी मिनिस्ट्री ने टारगेट फिक्स किया है कि वे अगले दो साल के अंदर रूरल एरियाज में 10 मिलियन ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स बनाएंगे। तो बगैर किसी प्रोपर व मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के यह कैसे मुमकिन होगा? मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि जो उन्होंने दो साल का टारगेट फिक्स किया है तो वह बगैर किसी मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के कैसे पूरा किया जा सकता है?

محترمہ محسنہ قدوائی : مائنے سبھاپتی مہودے، مائنے منتری جی نے اپنے جواب میں کہا ہے کہ انہوں نے میٹنگ میں چرچا کی ہے کہ رورل ایریاز میں کس طرح سے ٹیلی ڈینسٹی بڑھائی جائے اور کس طرح سے اس کو اور آگے گنی دی جائے۔ میں سمجھتی ہوں کہ ہماری ٹیلی فون انڈسٹری کا جو پھیلاؤ ہے، بڑھاؤ ہے، وہ سب راجیو جی، جو آج ہمارے بیچ میں نہیں ہیں، ان کی ہی دین ہے اور ان کا وژن تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ بہت سی ہماری کمپنیاں جیسے ایم۔ٹی۔این۔ایل۔ ہے، نہ صرف اپنے ملک میں، بلکہ دنیا میں بھی اس کا نام ہے۔ مائنے منتری جی نے میٹنگ میں یہ طے کیا کہ رورل ایریاز میں زیادہ سے زیادہ کام کیا جائے گا اور وہاں پر اور فیسلٹیز بڑھائی جائیں گی۔ میں مائنے منتری جی سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس وقت آپ کے پاس کوئی پروپر انفرااسٹرکچر نہیں ہے، کنیکٹوٹی نہیں ہے۔ لیکن یہ خوشی کی بات ہے کہ آج ہمارے رورل ایریاز کے لوگ بھی ایک دوسرے سے کمیونکیٹ کر سکتے ہیں، دوسرے ملکوں سے بات کر سکتے ہیں۔ لیکن اس وقت اتنا خراب انفرااسٹرکچر ہے، جس کے بارے میں میں مائنے منتری جی سے جاننا چاہتی ہوں کہ انہوں نے اس بارے میں کیا قدم اٹھائے ہیں، جس سے رورل ایریاز میں انفرااسٹرکچر مضبوط ہو سکے؟ مائنے منتری جی سے میں ایک اور بات جاننا چاہتی ہوں کہ ان کی منسٹری نے ٹارگیٹ فکس کیا ہے کہ وہ اگلے دو سال کے اندر رورل ایریاز میں 10 ملین براڈبینڈ سبسکرائیبکر بنائیں گے۔ تو بغیر کسی پروپر و مضبوط انفرااسٹرکچر کے یہ کیسے ممکن ہوگا؟ میں مائنے منتری جی سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جو انہوں نے دو سال کا ٹارگیٹ فکس کیا ہے تو وہ بغیر کسی مضبوط انفرااسٹرکچر کے کیسے پورا کیا جا سکتا ہے؟

Trasnslation in Urdu Script.

श्री सचिन पायलट: आदरणीय सभापति जी, माननीय सदस्या जी ने जो सवाल पूछा है, वह बहुत महत्वपूर्ण है और मैं आपके माध्यम से उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारत सरकार और दूर संचार मंत्रालय इस बात को बहुत गंभीरता से ले रहा है कि जो दूर संचार की क्रांति है, वह सिर्फ बड़े-बड़े शहरों तक सीमित न रहे और दूर-दराज के इलाकों में, खासकर के जो देहात का इलाका है, गांव का इलाका है, सीमा का क्षेत्र है, पहाड़ी इलाका है, वहां पर संचार की क्रांति करने का बीड़ा हम लोगों ने उठाया है।

सभापति जी, जब लगभग 15 वर्ष पहले दूर संचार क्रांति शुरू हुई, तो teledensity, The number of phone connections per 100 people, उस समय 15 साल पहले, हालांकि 2005 में सिर्फ 9 प्रतिशत थी, आज हम लगभग 44 प्रतिशत तक पहुंच गए हैं। जो बड़े-बड़े शहर हैं, दिल्ली है, मुम्बई है, कोलकात्ता है, चेन्नई है, यहां पर हमारा प्रतिशत सौ से ज्यादा है। लेकिन गंभीर समस्या इस बात की है कि जो ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में लोग रहते हैं, वहां पर हमारी teledensity 18.97 प्रतिशत है। हम लोगों ने कदम उठाए हैं, प्रभावी कदम उठाए हैं, हमारे मंत्रालय का एक बड़ा USO Fund है और आने वाले कुछ समय में सिर्फ बीएसएनएल के माध्यम से हम मार्च, 2010 तक 10 हजार नये टावर ग्रामीण क्षेत्रों में लगाने वाले हैं तथा मार्च, 2011 तक 15 हजार टावर हम बीएसएनएल के माध्यम से उन क्षेत्रों में लागायेंगे, जहां पर फोन या मोबाइल की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

सभापति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने अपने उद्बोधन में कहा था कि इस देश की सारी ग्राम पंचायतों को अगले तीन साल में हम ब्रॉडबैंड से जोड़ेंगे। इसके लिए पैसा, योजना, कार्यक्रम सब हमारा चालू है और बहुत जल्दी हम लोग अपने टारगेट को पूरा करेंगे। मैं आपके माध्यम से पुनः विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारा जो संकल्प है, उसको मैं एकबार दोबारा से रेखांकित करना चाहता हूं कि शहरों के अलावा ग्रामीण क्षेत्र पर सरकार का पूरा ध्यान रहेगा और जो दूर-दराज के इलाके हैं, उनको निश्चित रूप से हम संचार से जोड़ेंगे।

श्रीमती मोहसिना किदवई: सभापति महोदय, अभी माननीय मंत्री जी ने तसकरा Universal Service Obligation Fund का किया। मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहती हूं कि जो सरकारी आंकड़े मुझे मालूम हैं – 16 हजार करोड़ रुपये उस फंड में पैसा अभी है। यह पैसा रूरल एरिया में सबसिडी देने के लिए खासतौर पर है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि यह पैसा 16 हजार करोड़ रुपये आपकी kitty में है, यह सबसिडी देने के लिए है, तो क्या वजह है कि 16 हजार करोड़ रुपये खर्च नहीं हुए और अगर ये खर्च नहीं हुए, तो क्यों नहीं हुए हैं?

محترمہ محسنہ قدوائی : سبھا پتی مہودے، ابھی مانئے منتری جی نے Universal Service Obligation Fund کا تذکرہ کیا۔ میں مانئے منتری جی کو بتانا چاہتی ہوں کہ جو سرکاری آنکڑے مجھے معلوم ہیں - 16 ہزار کروڑ اس فنڈ میں پیسہ ابھی ہے۔ یہ پیسہ رورل ایریا میں سبسڈی دینے کے لئے خاص طور پر ہے۔ میں مانئے منتری جی سے جاننا چاہتی ہوں کہ یہ پیسہ 16 ہزار کروڑ آپ کی kitty میں ہے، یہ سبسڈی دینے کے لئے ہے، تو کیا وجہ ہے کہ 16 ہزار کروڑ روپے خرچ نہیں ہوئے اور اگر یہ خرچ نہیں ہوئے، تو کیوں نہیں ہوئے ہیں؟

Trasnslation in Urdu Script.

श्री सचिन पायलट: सभापति महोदय, सम्मानित सदस्या ने यह बिल्कुल सही बात कही है कि बहुत सारा पैसा हमारे पास उपलब्ध है। जब हम लोगों ने उस समय Licences mobile operators को दिए थे तब हमें यह आशंका थी कि हो सकता है कि जो private operators हैं, वे मुनाफा कमाने के लिए बड़े-बड़े शहरों में जायें, इसलिए हमने प्रावधान रखा था कि अपने पूरे आमदनी का कि ये सब कम्पनियां पांच प्रतिशत एक ऐसे फंड में जमा कराएं और उस फंड का सदुपयोग हम ग्रामीण क्षेत्र में संचार सुविधाओं का विस्तार करने के लिए उपयोग करेंगे। पहले यह लैंड लाइन के लिए था, फिर मोबाइल के लिए था और अब इसमें Broad band को भी जोड़ा गया है। हम लोगों ने एक प्रक्रिया चालू की है कि इस के डिप्लायमेंट के जो नियम, कानून हैं, उनको और सरल बनाया जाए और हम लोग सबसिडी देते हैं ताकि टॉवर लगाये जाएं, मोबाइल की सुविधा हो, लैंड लाइन की सुविधा हो और अब Broad band की भी। सभापति जी, मुझे लगता है कि इस पूरे देश में जिस तरह से संचार क्रांति मोबाइल के माध्यम से आई है, उसी तरह इंटरनेट और आई0टी0 की क्रांति आएगी ब्रॉडबैंड की जब वह वॉयरलैस होगा। हम लोग USO Fund का पैसा वॉयरलैस ब्रॉडबैंड में इस्तेमाल करें, इसके लिए हम प्रभावी कदम उठा रहे हैं और कहीं पर अगर कोई कठिनाई थी या उसके नियमों में कोई संशोधन करने की जरूरत थी, उसको हमारी सरकार करने वाली है।

MR. CHAIRMAN: Thank you.

SHRIMATI BRINDA KARAT: Very good.

MR. CHAIRMAN: Thank you. Mr. Vijayaraghavan. ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI BRINDA KARAT: Sir, Mr. N.K. Singh is there. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Sorry, Mr. Vijayaraghavan. Shri N.K. Singh.

SHRI A. VIJAYARAGHAVAN: Sir, you have called me.

MR. CHAIRMAN: He is there with the question. Mr. N.K. Singh.

SHRI N. K. SINGH: Well, Sir, considering that the media is awashed with only two types of stories on telecom, namely, high profitability of the telecom companies every month and the scam of the telecom sector, as an average consumer experiencing high drop rates of phones, growing irritation and very poor quality of telecom service, I would like to know from the Minister of Communications whether he has any credible plan for an independent telecom ombudsman who can redress this growing consumer irritation.

SHRI SACHIN PILOT: Mr. Chairman, Sir, first of all, I would like to take this opportunity to share with the House that our mobile services are growing at a very healthy rate and, I think, in a day or so, we will touch 50 crore mobile subscribers in the country. Having said that, I would like to inform the House that the increased competition and a number of players have made our call rates one of the cheapest in the world. Along with that comes the problem of congestion and call drops which is experienced by all operators, whether they are PSUs or private operators.

As regards the question put by the hon. Member, I can only speak for the regulatory mechanism that we have created in this country. In the case of the PSUs, whether it is the BSNL or the MTNL, we have asked these companies to take effective steps to curb the situation that arises out of call drops and congestion of the network. We are putting up more towers; we are updating our technology; we are investing more money to make sure that the frequencies are

aligned in such a way that the calls are much better in terms of quality. Sir, I think, the direct answer to this question is "No". But the role of the Government is to provide a level-playing field where competitors and many operators come, and the consumers get the cheapest and the best call rates that are available anywhere in the world; and I hope in the times to come even the private operators will be urged to invest more money to improve the quality of service. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Shri A. Vijayaraghavan. Please. ...*(Interruptions)*...

SHRI A. RAJA: Sir, I just want to add one thing. During the discussion that we had in the last session, I think hon. Members, Shri Venkaiah Naidu and Shrimati Brinda Karat, spoke about the call drops. Of course, we have our own system to maintain the records of call drops and the quality of the service is being maintained by the TRAI. In spite of that, considering the anguish shown by the hon. Members in this House, I made a statement through the ITU, when I attended it in Geneva, that a person who is getting a call, even if he says 'hello', there would be a droppage and immediately the consumer will be charged for one minute. I am with you. I have not at all compromised the views that have been expressed in this House. So, I made a statement as to why the consumer is going to be fined for the call drop that has been inculcated in the system of the service provider. We made an appeal that the call must be counted per second. Now it has been accepted. Of course, most of the companies are telling us that there will be a huge loss or moderate loss to the companies. I don't bother about it. Ultimately, the consumer should not be fined. This is the decision taken by the Government and, I think, you will all accept it. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Please. Shri. A. Vijayaraghavan.

SHRI A. VIJAYARAGHAVAN: Sir, this is a very serious issue. In a country like ours we have to expand the access to the telecom service where the Central Government and the BSNL have an important role to play. Unfortunately, as far as the reports are concerned, the BSNL, which made a profit of Rs. 4,231 crores in 2005-06, had suffered a loss of Rs. 1,277 crores in 2007-08 and it is expected that the loss will be more than Rs. 4,000 crores in the present year. In such a situation, there is an important role to be played by the BSNL. Unfortunately, it is under the scanner of the CBI. In such a situation, what steps are you going to take, at least, to protect the service providers, namely, MTNL and BSNL, which are making losses? There is a failure on the part of the Government. How are you going to play your — the Government, the BSNL and the MTNL — roles? The BSNL and the MTNL are already in the red. How are you going to save them? Please give a proper reply to this.

SHRI SACHIN PILOT: Mr. Chairman, Sir, this question does not relate directly to BSNL and MTNL. However, I will try my level best to answer his question. Sir, BSNL and MTNL, I think, are doing a commendable job. One must not forget the kind of responsibility being thrust upon our PSUs to discharge some of the social obligations also. Just to make a point, BSNL pays 33 per

cent of all its income to its employees. There are about three lakh employees in BSNL. If you compare that to the largest mobile service provider in India, they are hiring only 20,000 people. The average salary that they pay from their income is between five and eight per cent. The PSUs have a large historical manpower which we have to sustain, which we have to keep. However, so far as the question about the steps taken by BSNL is concerned, I would like to point out on the floor of the House that the market share of BSNL in landline is 77 per cent; in broadband, it is 60 per cent, for mobile service, it is 13.3 per cent. This is for BSNL. So far as MTNL is concerned...

SHRI A. VIJAYARAGHAVAN: Every year, it is coming down.

SHRI SACHIN PILOT: Sir, the market share is coming down because earlier BSNL and MTNL had a monopoly. We have allowed private operators to come and operate. Because there is increased competition, the market share is bound to come down. But I am happy to report that in last 12 months, in the last four quarters, the rate of decline of these PSUs is now being mitigated. We are taking effective steps to make sure that BSNL and MTNL maintain their effective position in the market. . Sir, I would like to illustrate two-three points. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Please be patient. Listen to the Minister.

SHRI SACHIN PILOT: Mr. Chairman, Sir, I would like to illustrate two-three points. We have taken initiative on behalf of the Government of India through BSNL to make sure that these companies remain robust and dynamic and perform their functions. There are 13 lakh points of sale all over India where these mobile SIM cards and other items are sold. As of now, BSNL's footprint is only 2.5 lakhs. We are having increased marketing efforts to make sure that we reach about 3.5 lakh outlets so that our market share of footprint, our presence all over India, increases everyday. We have got in touch with BCG which is one of the top firms. BSNL is consulting with them. We are having franchise modes. We are pushing ourselves and making efforts. We are having very, very attractive packages for our customers. I can assure the hon. Members on the floor of this House that we will spare no effort to make sure that BSNL and MTNL remain in that paramount position. We will give them all the support from the Government side to make sure that they give better and better service.

श्री विजय कुमार रूपाणी: सभापति जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि BSNL के बारे में बहुत सारे लोग हास्यास्पद बातें बताते हैं कि इसका पुअर नेटवर्क है, आउट ऑफ कवरेज एरिया है। उसका कारण है कि हमारे वेस्टर्न साइड में आई.टी.आई. कंपनी के उपकरण, जो BSNL खरीदती है, उनके द्वारा सब नेटवर्क किया जा रहा है। इस आई.टी.आई. कंपनी ने कभी भी टाइम लिमिट के अंदर सप्लाई नहीं किया है। उनकी सप्लाई और इन्स्ट्रूमेंट भी बहुत पुअर हैं। बाकी रीजन में, जहां सभी इम्पोर्टेंट मशीनरी लगाई हैं, वहां ठीक चल रहा है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि आपने इस संबंध में आई.टी.आई. कंपनी पर क्या कार्यवाही की है? मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि BSNL का जो heighest नेटवर्क है, उस नेटवर्क का इन्फ्रास्ट्रक्चर भी आपने प्राइवेट कंपनी को यूज करने के लिए दिया है, इसमें कितना मुनाफा BSNL को मिल रहा है? हमारी जानकारी है कि इन्फ्रास्ट्रक्चर का 25% ...(**व्यवधान**)... 75% उनको दे रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है?

MR. CHAIRMAN: Please answer one question.

SHRI SACHIN PILOT: Sir, the supplementary question does not relate to this question. If he wants any specific details, I would request him to meet me and give me in writing. I will submit those details to him.

श्री अवतार सिंह करीमपुरी: सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि BSNL के नेटवर्क की जो हालत है, क्या ये खुद BSNL का यूज करते हैं या किसी और कंपनी का कनेक्शन ले रखा है? हम मंत्री जी से हाउस में यह एश्योरेंस चाहते हैं कि BSNL के नेटवर्क की जो व्यवस्था है, वह बहुत पुअर है। आपने यह तो कर दिया गया है कि कॉल चार्जेस एक मिनट की बजाय एक सैकिण्ड पर आ जाएंगे...(व्यवधान)...

श्री सभापति: सवाल पूछ लीजिए।

श्री अवतार सिंह करीमपुरी: क्या इस व्यवस्था को सुधारने के लिए भी कोई एफ्टर्स जुटाए जाएंगे? क्या इस व्यवस्था को सुधारा जाएगा? धन्यवाद।

SHRI SACHIN PILOT: Sir, again this supplementary does not relate to the main question directly. But I can assure the hon. Member, through you, Sir, that the problems we face सभापति जी, ग्रामीण क्षेत्र में हमें ज्यादा दिक्कत आती है। जो मोबाइल के टावर होते हैं, वहां पर कभी-कभी बिजली की सप्लाई नहीं होती है। बिजली की सप्लाई नहीं होने से वे टावर्स काम में नहीं आ सकते हैं। हमने वहां व्यवस्था की है। हम लोग जनरेटर देते हैं, डीजल भी उपलब्ध करवाते हैं, लेकिन अगर पावर सप्लाई बेहतर होगी..

श्री साबिर अली: सभापति जी, बिहार में...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: बैठ जाइए। आप जवाब सुन लें। ...(**व्यवधान**)...

श्री साबिर अली: सभापति जी...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: साबिर अली जी, आप बैठ जाइए प्लीज़ ...(**व्यवधान**)... आप बैठ जाइए, आप जवाब सुन लीजिए ...(**व्यवधान**)... आप जवाब सुन लीजिए, आपकी बारी नहीं आई है।

श्री सचिन पायलट: मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूँ ...(**व्यवधान**)... मेरा निवेदन है कि अगर मोबाइल टावर्स को सही बिजली उपलब्ध होगी, तो निश्चित रूप से वे काम करेंगे। मैं आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करना चाहता हूँ कि अपनी-अपनी राज्य सरकारों से भी निवेदन करें कि वे बिजली का उत्पादन बढ़ाएँ, ताकि हमारे मोबाइल टावर्स काम कर सकें।

पिछड़े राज्यों का विकास

*107. **श्री रवि शंकर प्रसाद**:
श्री शिवानन्द तिवारी:††

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अपनी प्रति व्यक्ति आय और वार्षिक वृद्धि दर के आधार पर बिहार, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश इत्यादि राज्य पिछड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2003 से 2008 तक की अवधि में इन राज्यों में अनुमानित प्रति व्यक्ति औसत आय और वार्षिक वृद्धि-दर कितनी-कितनी रही है;

---

††सभा में यह प्रश्न श्री शिवानन्द तिवारी द्वारा पूछा गया।